संख्या:342/2022/1179/35-4-2022/001-35-4099/81/2022

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 सितम्बर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-मोहम्मदाबाद के ग्राम गोडउर में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-108/2020/914/35-4-2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुमोदित लागत रू0 1082.77 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू0 270.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक: 416/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2022, दिनांक 02 सितम्बर, 2022 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में देय रू. 270.70 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि
विधान सभा क्षेत्र-मोहम्मदाबाद के ग्राम गोडउर, गाजीपुर में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कार्य	1082.77	270.70	270.70

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत बृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,70,70,000 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:342/2022/1179(1)/35-4-2022/001-35-4099/81/2022 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/व्यावसायिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
9- निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।
14- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण् विभाग, गाजीपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।